

○वर्ष-23

○अंक-270

○दैनिक प्रभात संस्करण

○जयपुर, बुधवार 04 जून , 2025

○पृष्ठ-4

○मूल्य: 2.50

सड़कों को सुचारु रखें ताकि आमजन को परिवहन में बाधा न आये-दिया कुमारी

जयपुर। प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मानसून में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून पूर्व ही सड़कों को संधारित रखने के लिए की जाने वाली सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली जाये ताकि बरसात के सीजन में परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुचारु एवं निर्बाध रहें। उपमुख्यमंत्री ने मंगलवार को निर्माण भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्थानों पर पानी जमा होता है वहां कच्ची ड्रेन खोदकर पानी निकासी की व्यवस्था रखें और पानी जमा नहीं होने दे। इसके साथ ही यदि किसी सड़क मार्ग पर बरसात के कारण कटाव या खड्डे हो गये हो तो उन्हें प्रारम्भिक स्तर

ही भरवा दे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रत पुलिया, रपट आदि की मरम्मत के लिए जो स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं उन कार्यों को जल्दी पूरा करवा ले। उन्होंने कहा है कि यदि बरसात के मौसम में संबंधित अधिकारी तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम स्थापित करवाकर अति वर्षा व व बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने की सभी आवश्यक तैयारिया पूरी कर ले। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में जितने भी अटल पथ व अन्य सड़के बनायी जाये उनके साथ नाली बनाने का भी प्रावधान रखें ताकि जल भराव के कारण बार बार सड़क टूटने की समस्या से निजात मिल सकें।

अब हर सप्ताह संभाग वार समीक्षा होगी-

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं की प्रदेश की सड़क परियोजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए इसी माह से हर सप्ताह संभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में उस संभाग की सभी सड़क परियोजनाओं, बजट घोषणाओं सहित सभी कामों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।



मुख्य सचिव ने की राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

जयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की द्वि-साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने तीव्र भूमि आवंटन की प्रक्रिया को एमओयू क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में भूमि बैंकों के निर्माण प्रक्रिया को तेज करें। पंत ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि वह उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर (अजमेर) आदि प्रमुख जिलों में सरकारी भूमि की नीलामी एवं आवंटन के लिए उपयुक्त प्रावधान तैयार करें। उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ विभागों को एमओयू के शीघ्र क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में नियामक ढांचे को सरल बनाने की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। एमओयू क्रियान्वयन पर द्वि-साप्ताहिक समीक्षा बैठक के अतिरिक्त, पंत ने भारत सरकार द्वारा निर्देशित अनुपालन में कमी और विनियमन शिथिलीकरण अभ्यास की प्रगति की समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता की। विभागीय सचिवों ने पंत को केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए प्रमुख के लिए जीआईएस-आधारित भूमि बैंक का विकास, भवन विनियमों में संशोधन, सिंगल विंडो अप्रूवल प्रणाली, लघु अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को डी-लाइसेंस करना, महिलाओं को रात्रि शिफ्ट में और कुछ खतरनाक कारखाना एवं बायोलर विभाग, श्रम विभाग, रीको, बीआईपी, राजस्व विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएच), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी) सहित विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर कार्य किया जा रहा है, उनमें उद्योगों



लाख करोड़ के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च में आयोजित 'IMPACT 1.0' कार्यक्रम में सरकार ने घोषणा की थी कि सम्मेलन के तीन माह के भीतर ही 73.08 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे जा चुके हैं। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों में लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार, विधि एवं कानूनी मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव ब्रजेन्द्र कुमार जैन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त रोहित गुप्ता तथा राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान रेरा का फैसला-बिल्डर को एग्रीमेंट और जमा राशि पर ब्याज देने का आदेश

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में शिकायतकर्ता हेमलता रांका के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, कोरल इंफ्रा गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोरल शुभ निवास परियोजना में आवासीय इकाई के रद्दकरण को रद्द कर दिया है। रेरा की अध्यक्ष वीनू गुप्ता की बेंच में हुए इस फैसले में बिल्डर को बिक्री समझौता निष्पादित करने और देरी के लिए 11.10 प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। यह शिकायत रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत दायर की गई थी। शिकायतकर्ता हेमलता रांका ने लाभ टॉवर में यूनिट संख्या 302 बुक की थी। यह यूनिट मूल रूप से प्रकाश रांका के नाम पर 17 मई 2017 के आवंटन पत्र द्वारा बुक की गई थी, जिसे बाद में 27 अप्रैल 2017 में बदल दिया गया। प्रकाश रांका ने 25 जून 2021 के एक हलफनामे के माध्यम से आवंटन रद्द करने और



सेवा हुई। बिल्डर के वकील ने प्रारंभिक आपर्ति उठाते हुए कहा कि जब पार्टियों के बीच कोई बिक्री समझौता निष्पादित नहीं किया गया है, तो अधिनियम की धारा 18 लागू नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी दावा किया कि 27 अप्रैल 2017 का आवंटन फॉर्म बिल्डर द्वारा जारी नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यूनिट को 12 मार्च 2023 को समय पर भुगतान न करने के कारण रद्द कर दिया गया था और तीसरे पक्ष के अधिकार पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना में देरी फोर्स मेज्योर के कारणों से हुई थी और परियोजना अब समाप्त हो चुकी है। बिल्डर 2021 से प्राप्त धन को ब्याज सहित वापस करने को तैयार था। प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 13 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने बिक्री समझौता निष्पादित किए बिना आर्बिट्रियों से कुल बिक्री मूल्य का 10% से अधिक स्वीकार किया है। प्राधिकरण ने यह भी देखा कि 25 जून 2021 को एक हलफनामा निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा हेमलता रांका को प्रकाश रांका के स्थान पर आर्बिट्री के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। बिल्डर ने इस हलफनामे को स्पष्ट रूप से अस्वीकार या विवादित नहीं किया

तर्क दिया कि रद्द करने का ईमेल बिना किसी पूर्व अनुस्मारक पत्र के भेजा गया था और यह शिकायतकर्ता के पति को भेजा गया था, न कि शिकायतकर्ता को, जिससे अनुचित मेज्योर के कारणों से हुई थी और परियोजना अब समाप्त हो चुकी है। बिल्डर 2021 से प्राप्त धन को ब्याज सहित वापस करने को तैयार था। प्राधिकरण ने पाया कि बिल्डर ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 13 का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने बिक्री समझौता निष्पादित किए बिना आर्बिट्रियों से कुल बिक्री मूल्य का 10% से अधिक स्वीकार किया है। प्राधिकरण ने यह भी देखा कि 25 जून 2021 को एक हलफनामा निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा हेमलता रांका को प्रकाश रांका के स्थान पर आर्बिट्री के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। बिल्डर ने इस हलफनामे को स्पष्ट रूप से अस्वीकार या विवादित नहीं किया

नकली बीज के खिलाफ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा अभियान, श्रीगंगानगर में छापेमारी से मचा हड़कंप

श्रीगंगानगर। राजस्थान में खेती-किसानी से जुड़े माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सख्त तेवर अपनाए हैं। इस बार उनका निशाना बने हैं नकली बीज बेचने वाले कारोबारी, जो पंजाब सीमा से लगे इलाकों में सक्रिय हैं। 3 जून को श्रीगंगानगर जिले के ऋद्धट्टह औद्योगिक क्षेत्र में कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम के साथ किरोड़ी लाल मीणा ने औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान कई बीज भंडारों में अनियमितताएं सामने आईं, नकली बीज जब्त हुए और फर्जी ब्रांडिंग की पोल खुली।



उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि खेती से जुड़ी हर आपूर्ति को शुद्ध और भरोसेमंद बनाना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब उन्होंने नकली बीज के खिलाफ मोर्चा खोलकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई एक मुहिम का हिस्सा है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक कृषि आपूर्ति में पूरी

अजमेर जिले के किशनगढ़ में 12 स्थानों पर छापेमारी कर मिलावटी खाद का भंडाफोड़ कर चुके हैं। पारदर्शिता न आ जाए। श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई -3 जून की सुबह श्रीगंगानगर के

बीज भंडार बिना वैध लाइसेंस के कार्यरत पाए गए। गुणवत्ता में खामी -प्रारंभिक जांच में कई बीज नमूने निम्न गुणवत्ता के निकले। फर्जी ब्रांडिंग का खेल-कुछ स्थानों पर बीज पैकिंग पर प्रामाणिक ब्रांड नाम छापकर नकली बीज बेचे जा रहे थे।

सैंपल लैब भेजे गए, विस्तृत जांच शुरू

छापेमारी में जब्त किए गए बीजों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। इनकी रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने बीज पूरी तरह नकली या अनुपयुक्त थे। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ Essential Commodities Act, Seed Act और

Fraudulent Practices जैसे कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री का बयान -किसानों के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं होगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस से बातचीत में कहा पंजाब से सटे इस इलाके में नकली बीज सप्लाई हो रहा है। हम किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे. नकली खाद और नकली बीज बेचने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा. किसानों की मेहनत और उनकी फसल के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ईमानदार भारत, आत्मनिर्भर किसान' के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आक्रामकता के शिकार बच्चों की पीड़ा और दर्द को समझें

(लेखक- ललित गर्ग) (आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अन्तर्राष्ट्रीय दिवस- 4 जून, 2025)

बच्चे दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा हैं और किसी भी समाज की भलाई के लिए बच्चों का सुरक्षित एवं संरक्षित होना जरूरी हैं। वे समाज के सबसे कमज़ोर सदस्य हैं, जिन्हें निष्फ़टक, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए समान अवसर दिए जाने और उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, हर साल संघर्ष और युद्धों के कारण बच्चों की एक बड़ी संख्या हिंसा, विस्थापन, अपंगता और दुर्व्यवहार का शिकार होती है।

बच्चों को देश एवं दुनिया के भविष्य की तरह देखा जाता है। लेकिन उनका यह बचपन रूपी भविष्य लगातार हो रहे युद्धों की विभीषिका, त्रासदी एवं ख़ौफनाक स्थितियों के कारण गहन अंधेरो एवं परेशानियों से घिरा है। आज का बचपन हिंसा, शोषण, यौन विकृतियों, अभाव, उपेक्षा, नशे एवं अपराध की दुनिया में घंसता चला जा रहा है। बचपन इतना उपेक्षित, प्रताड़ित, डरावना एवं भयावह हो जायेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्यों बचपन बदहाल होता जा रहा है? बचपन इतना उपेक्षित क्यों हो रहा है? बचपन के प्रति न केवल अभिभावक, बल्कि समाज, सरकार एवं युद्धरत देशों की सत्ताएं इतनी बेपरवाह कैसे हो गयी है? ये प्रश्न 4 जून को आक्रामण के शिकार हुए मासूम बच्चों के दिवस को मनाते हुए हमें झकझोर रहे हैं। इस दिवस को मनाने की प्रासंगिकता आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा महसूस हो रही है। इस दिवस का उद्देश्य आक्रामकता के शिकार बच्चों की पीड़ा और उनके दर्द को स्वीकार करना, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराना, समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, बच्चों के साथ हिंसा रोकने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास करना, बच्चों के लिए सुरक्षित, हिंसामुक्त और अनुकूल वातावरण बनाना एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें हिंसा से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत 1982 में की थी, जब फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों पर हुए अत्याचारों के बाद यह दिवस घोषित किया गया था, जिसे मनाते हुए हमें दुनिया भर में बच्चों द्वारा झेले गए दर्द को स्वीकारना होगा, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

बच्चे दुनिया की आबादी का एक चौथाई हिस्सा हैं और किसी भी समाज की भलाई के लिए बच्चों का सुरक्षित एवं संरक्षित होना जरूरी हैं। वे समाज के सबसे कमजोर सदस्य हैं, जिन्हें निष्फटक, खुशहाल और सफल जीवन

जीने के लिए समान अवसर दिए जाने और उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, हर साल संघर्ष और युद्धों के कारण बच्चों की एक बड़ी संख्या हिंसा, विस्थापन, अपंगता और दुर्व्यवहार का शिकार होती है। यह केवल इस बात को साबित करता है कि बच्चों पर किसी भी संघर्ष का गंभीर एवं घातक प्रभाव पड़ता है। निश्चित ही रूस एवं यूक्रेन, गाजा एवं इजरायल जैसे लम्बे समय से चल रहे युद्धों के कारण हर दिन, दुनिया भर में बच्चे अकथनीय भयावहता एवं त्रासदियों का सामना कर रहे हैं। वे अपने घरों में सोने या बाहर खेलने, स्कूल में पढ़ने या अस्पतालों में चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में सुरक्षित नहीं हैं। हत्या और अपंगता, अपहरण और यौन हिंसा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले नयी बन रही विश्व संरचना के लिये गंभीर चुनौती है। बच्चे चौंका देने वाले पैमाने पर युद्धरत दलों के निशाने पर आ रहे हैं।

हाल के वर्षों में, कई संघर्ष एवं युद्ध क्षेत्रों में, महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण बच्चों के खिलाफ उल्लंघन की संख्या में वृद्धि हुई है। संघर्ष, युद्ध, हिंसा एवं महामारियों से प्रभावित देशों और क्षेत्रों में रहने वाले 250 मिलियन बच्चों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हिंसक अतिवादियों द्वारा बच्चों को निशाना बनाने से बचाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयासों एवं संकल्पों की जरूरत है ताकि बच्चों के बेहतर भविष्य को सुरक्षित एवं सुनिश्चित किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के नए एजेंडे में पहली बार बच्चों के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य शामिल था और बच्चों के दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण को समाप्त करने के लिए कई अन्य हिंसा-संबंधी लक्ष्यों को मुख्यधारा में शामिल किया गया। विश्वस्तर पर बालकों के उन्नत जीवन के ऐसे आयोजनों के बावजूद आज भी बचपन उपेक्षित, प्रताड़ित एवं नारकीय बना हुआ है, आज बच्चों की इन बदहाल स्थिति की प्रमुख वजहें हैं, वे हैं-सरकारी योजनाओं का कागज तक ही सीमित रहना, बुद्धिजीवी वर्ग व जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, दुनिया की महाशक्तियों की ओर से बच्चों के ज्वलंत प्रश्नों पर आंख मूंद लेना, इनके

प्रति समाज का संवेदनहीन होना एवं गरीबी-शिक्षा के लिये जागरूकता का अभाव है।

युद्धों एवं ऐसी ही स्थितियों में 11,649 बच्चे मारे गए या अपंग हो गए। अधिकांश मामलों में, विस्फोटक आयुध और बारूदी सुरंगों का उपयोग आबादी वाले क्षेत्रों में किया गया, जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई और वे अपंग हो गए। 8,655 बच्चों का इस्तेमाल संघर्ष में किया गया और 4356 का अपहरण किया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या कांगो, सोमालिया और नाइजीरिया के लोकतांत्रिक गणराज्य में पायी गयी। पीड़ितों में से लगभग 30 प्रतिशत लड़कियां थीं। 1,470 बच्चे यौन हिंसा के शिकार हुए है। संघर्ष में यौन हिंसा कलंक और कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सबसे कम रिपोर्ट की जाने वाली गंभीर हिंसा है। 90 प्रतिशत से अधिक यौन हिंसा लड़कियों के खिलाफ की गई, जो यौन हिंसा और जबरन विवाह से असमान रूप से प्रभावित हैं, हालांकि लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। 2022 से 2023 तक मानवीय सहायता से वंचित करने की घटनाओं में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो अवसर अन्य गंभीर उल्लंघनों में वृद्धि के साथ मेल खाती है। 2024 के लिए, मानवीय सहायता से वंचित करने की घटनाओं में कई संदर्भों में गिरावट आने की उम्मीद है, विशेष रूप से अफ़गानिस्तान, म्यांमार और सूडान में मानवीय संगठनों और कर्मियों पर नियंत्रण बढ़ाने वाले प्रतिबंधात्मक नियमों को अपनाने के कारण। 2023 तक, स्कूलों पर हमलों में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोफी अन्नान ने एक बार कहा था, ‘दुनिया में बच्चों के साथ जो भरोसा है, उससे ज्यादा पवित्र कोई भरोसा नहीं है। यह सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कर्तव्य नहीं है कि उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए, उनके कल्याण की रक्षा की जाए, उनका जीवन भय और अभाव से मुक्त हो और वे शांति से बड़े हो सकें।’

बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघनों को समाप्त करना और रोकना बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर जनादेश का मुख्य हिस्सा है। बच्चों को शत्रुता से बचाने का सबसे प्रभावी



तरीका उन दबाव और खींचतान वाले कारकों को खत्म करना है जो उन्हें सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जब वे हँसते-मुस्कुराते हैं। बच्चे यदि तनावरहित रहते हैं तो चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे भी पीड़ा महसूस करते हैं। यह पीड़ा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक किसी भी तरह के शोषण से पैदा होती है। बच्चे खुश, स्वस्थ और सुरक्षित होने चाहिए। उन्हें जाने-अनजाने में भी कोई पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए। बच्चों की खुशी में देश एवं दुनिया का उज्ज्वल भविष्य छुपा है। कुछ बीमार मानसिकता यानी पीडोफिलिया ग्रस्त व्यक्ति मासूम बच्चों को क्रूरतम मानसिक व शारीरिक यातनाएं देने में आनंद की प्राप्ति करता है तथा उसके लिए यह एक ऐसा नशा बन जाता है कि वह बच्चों को यातनाएं देने कि क्रूरतम विधियां इजाद करता जाता है जिसमें बच्चों के साथ सेक्स, शरीर को चोटिल करना-काटना, जलाना, यहाँ तक कि उनके टुकड़े-टुकड़े कर उनके मांस तक खाना शामिल है। कुछ देशों में बच्चों को ऊंट की पीथ पर बान्धकर ऊंटों को दौड़ाया जाता है जिससे बच्चे कि चीत्कार-चीख से वहां के लोग आनन्द एवं मनोरंजन की प्राप्ति करते हैं, यह भी पीडोफिलिया का ही एक उदाहरण है। इन क्रूर एवं अमानवीय स्थितियों का मासूम बच्चों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ता है और इन कमजोर नींवों पर हम कैसे एक सशक्त दुनिया की कल्पना कर सकते हैं?

प्रेम और घृणा के बीच मानवता का सफर

अंतर्मन/ श्याम सखा 'श्याम'

प्रेम और घृणा—हमारे भावनात्मक और सामाजिक ब्रह्मांड की दो सबसे शक्तिशाली शक्तियां—न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को आकार देती हैं, बल्कि पूरी सभ्यताओं के उदय और पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक उदाहरण प्रसिद्ध इतिहासकार—युवाल नोआ हराרי, इस्राइली विद्वान और होमो सेपियंस पुस्तक के लेखक—ने साझा किया है।

हरारी कहते हैं कि यदि आप एक इंसान और एक गोरिल्ला को किसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दें, तो संभव है कि गोरिल्ला इंसान से अधिक समय तक जीवित रहे—यहां तक कि वह इंसान को मार भी सकते हैं। लेकिन यदि आप दस इंसानों और सी गोरिल्लाओं को उसी द्वीप पर छोड़ दें, तो लगभग निश्चित है कि इंसान जीतेंगे। वजह है कि इंसान संगठित हो सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि सामूहिक निर्णय ले सकते हैं। यही सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता मानव समाज की नींव बनी ,जो सबसे पहले परिवार के रूप में प्रकट हुई।

कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब एक पुरुष और एक स्त्री साथ रहने का निर्णय लेते हैं— बच्चे का पालन-पोषण करते हैं, भोजन, आश्रय और भावनात्मक संबंध साझा करते हैं। यही सह-अस्तित्व मानव इतिहास का पहला सहयोगी निर्णय था। इसी पहले प्रेम और सहयोग की इकाई से कबीले बने, संस्कृतियां विकसित हुईं, धर्मों का उदय हुआ, और राष्ट्रों की नींव पड़ी। हम इस विचार को आदम और हव्वा की प्राचीन कथा में भी प्रतीक रूप में देख सकते हैं—एक ऐसी कहानी जिस चाहे आप धर्म में विश्वास करें या नहीं, एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को प्रकट करती है। यह प्रेम, प्रलोभन, साथ, गलती और परिणाम की कहानी है।

बीसवीं सदी के दार्शनिक जिड्डू कृष्णमूर्ति ने क्रांतिकारी दृष्टिकोण

प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि आदम और हव्वा का मिलन—या आधुनिक विवाह संस्था—प्रेम पर नहीं, बल्कि आवश्यकता पर आधारित है। पारस्परिक निर्भरता, सुविधा, और यहां तक कि स्वार्थ भी इसमें शामिल हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘अधिकांश लोगों के लिए प्रेम का अर्थ है - आराम, सुरक्षा और जीवनभर की भावनात्मक संतुष्टि की गारंटी।’ साथ ही, विवाह में भी विश्वास और आपसी संतोष की एक नाजुक उम्मीद निहित होती है। यदि हम विवाह संस्था के इतिहास को देखें, तो पता चलता है कि यह एक पवित्र बंधन के रूप में शुरू होकर धीरे-धीरे अनुबंध और फिर कानूनी युद्धभूमि बन गई। तलाक—जो कुछ आदिम समाजों में भी मौजूद था—सबसे पहले यूनानी-रोमनों ने कानून में दर्ज किया। बाद में, ईसाई और हिंदू धर्म ने इसे पाप माना, जबकि इस्लाम ने तलाक को स्वीकार किया, लेकिन अंतिम उपाय माना। दिलचस्प बात यह है कि इस्लाम ने पुरुषों के लिए तलाक की प्रक्रिया को सरल भी बनाया।

समय के साथ, नवीनता, परिवर्तन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इच्छा आजीवन प्रतिबद्धता के आदर्श से अधिक बलवती हो गई। और आज तलाक एक वैश्विक वास्तविकता बन चुका है—लगभग सामान्य। विवाह संस्था का पतन इसलिए नहीं हुआ कि मनुष्यों ने प्रेम करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि प्रेम की परिभाषा बदल गई है। अहम प्रेम को केवल एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि प्रेम मुक्त करे, न कि बंधन में डाले; समृद्ध करे, न कि दास बनाए।

व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो परिवार, जो प्रेम और विश्वास से जन्मा था, वही बीज बना जिससे कबीले, समाज, धर्म और राष्ट्र



विकसित हुए। विश्वास ने कानूनों को जन्म दिया, और मानव अधिकारों की अवधारणा का आधार रखा। लेकिन याद रखें—प्रकृति और जीवन द्वैत के सिद्धांत पर चलते हैं। रात के बाद दिन आता है, प्रकाश अंधकार में बदलता है, और जहां प्रेम होता है, वहां उसकी छाया भी होती है। वह छाया है - ईर्ष्या, भय, और अंततः घृणा। इसी तरह, विश्वास से शंका उत्पन्न

होती है, फिर अविश्वास, और अंततः भय। ये तीनों—घृणा, भय और अविश्वास—मानव सभ्यता के सबसे बड़े शत्रु हैं। इन्होंने परिवारों को तोड़ा, समाजों को चकनाचूर किया, और सदियों तक युद्ध कराए।

अब्राहमिक धर्मों—यहूदी, ईसाई और इस्लाम—को देखें। तीनों एक ही आध्यात्मिक पूर्वज, मिलते-जुलते ग्रंथ और समान भविष्यवक्ताओं को मानते हैं। फिर भी सदियों से वे ईश्वर के नाम पर युद्धरत रहे। क्या यह विडंबना नहीं है? कि वे धर्म जो विश्वास, प्रेम और शांति पर आधारित हैं, वही युद्ध, विभाजन और असहिष्णुता का कारण बने? यही है मानव विकास की दुखद विडंबना। हम करुणा कर सकते हैं, फिर भी घृणा पालते हैं। हम संबंध चाहते हैं, फिर भी भय की दीवारें खड़ी करते हैं। हम विश्वास बनाते हैं, पर अविश्वास करने में जल्दबाजी करते हैं। तो फिर समाधान क्या है? उत्तर प्रेम को अस्वीकार करने में नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से परिभाषित करने में है। संस्थाओं जैसे परिवार और विवाह को नष्ट करने में नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी, स्वतंत्रता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से पुनर्जीवित करने में है। यह हमारे बच्चों को यह सिखाने में है कि प्रेम के उजाले और उसकी छाया—दोनों को समझें। विश्वास को महत्व दें, लेकिन जब वह टूटे, तो माफ करने का साहस रखें। दूसरों को शत्रु नहीं, बल्कि जीवन यात्रा के सहयात्री समझें।

(चिंतन-मनन)

भलाई का भाव होता है यज्ञ



एक भाव होता है मेरा दूसरा है मेरे लिए और तीसरा है सबके लिए। मेरा मैं इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता रहता है और ये पक्का कर लेता है कि मेरे पास जो है, वो केवल मेरा है, मैंने कमाया है, मुझे मिला है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यह सोच अज्ञानी लोगों की होती है, जो हमारे अहंकार को बनाये रखती है। मेरे लिए अर्थात इंसान सोचता है कि

जो भी मेरे पास है, ये मेरा नहीं बल्कि मेरे लिए है। इसका स्वामी मैं नहीं बल्कि ये सब मुझे इस्तेमाल करने के लिए मिला है। वो इसी भाव को मन में रखता है। यह सोच मध्यम दर्जे के लोगों की होती हैं।

तीसरा भाव है सबके लिए मतलब जो मेरे पास है, वो मेरा ही नहीं और मेरे लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विचार उत्तम दर्जे के इंसानों का

होता है। इसी को यज्ञ कहा जाता है। जब मन में सबकी भलाई का भाव हो वही यज्ञ है। जो सबका ध्यान रखकर बाद में अपना सोचता है वही श्रेष्ठ इंसान है। इस तरह का यज्ञ अहंकार को गला देता है। ऐसी भावना के साथ साधना करने वाला ब्रह्म को पा लेता है। जो मनुष्य केवल मेरा-मेरा में ही फंसा रहता है, वो ना तो इस जन्म में सुख पाता न ही मरने के बाद परलोक में।

वित्तर मंथन

(लेखक- सनत जैन)

सीमावर्ती राज्यों और पड़ोसी देशों से भारत को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। पिछले एक दशक में भारत के पड़ोसी देश और पूर्वोत्तर राज्य सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका भारत के लिए चुनौती बने हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टरपंथी तेजी के साथ सक्रिय हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना पर कट्टरपंथियों का प्रभाव है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरीके की अशांति लंबे समय से फैली हुई है, भारत को आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से यह चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। भारत को वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से सबसे बड़ा खतरा है। हाल ही में चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन किया है। उसे आर्थिक और सामरिक मदद दी है। उसके कारण भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। पिछले एक दशक में चीन ने भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ बड़े-बड़े अनुबंध किए हैं। अरबों डॉलर का कर्ज

आंतरिक और बाह्य चुनौतियों से जूझता भारत

भारत के पड़ोसी देशों को दिया है। सुरक्षा की दृष्टि से चीन ने भारत के पड़ोसी देशों के सामरिक महत्व के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में दुनिया के देशों के बीच बढ़ता तनाव और उस पर भारत का पाकिस्तान और चीन के बीच जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, वह भारत के लिए चिंताजनक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर अशांत राज्य हैं। विशेष रूप से मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। यहां पर कुकी और मैतई के बीच पिछले दो वर्षों से हिंसक वारदात हो रही हैं। दोनों समुदायों के बीच भारी तनाव बना हुआ है। भारत का सुरक्षा बल जम्मू- कश्मीर, मणिपुर और बांग्लादेश की सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। ऐसी स्थिति में जब तृतीय विश्व युद्ध जैसे हालात तैयार हो रहे हों, ऐसे समय पर भारतीय सेना के लिए सीमावर्ती राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। भारत के सभी पड़ोसी देश चीन के प्रभाव में हैं। भारत पड़ोसी देशों के बीच में बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है। चीन के साथ भारत का रिश्ता वैसा मधुर नहीं रहा, जो पिछले वर्षों में था। हाल ही में पहलगाम

में हुई घटना के बाद जब भारत ने पाकिस्तान का जल रोकने का निर्णय लिया तो उसके बाद चीन ने भारत को चेतावनी दी। यदि उसने पाकिस्तान का पानी शुरू नहीं किया, तो वह ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत के लिए रोक देगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन के अत्याधुनिक हथियारों से भारत के ऊपर हमला किया। चीन पाकिस्तान का रक्षा कवच बनकर सामने आया। जिस तरह से भारत को चीन और पाकिस्तान से लगातार चुनौती मिल रही है, उसके कारण भारत की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सेकड़ों राष्ट्राध्यक्ष भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई भी राष्ट्र भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा नहीं हुआ। यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। यह भारत की विदेश नीति की विफलता भी है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाकर नहीं रख पाया। वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से चीन के मुकाबले भारत की इमेज बनी है, वह भारत के लिए सबसे नुकसानदेह साबित हो रही है। पुरानी कहावत है, स्त्री और सत्ता ताकतवर हाथों में ही सुरक्षित रहती है। चीन इस समय

एशिया का सबसे ताकतवर देश है। चीन का व्यापार दुनिया के सभी देशों के साथ हो रहा है। कुछ मामलों में चीन की मोनोपॉली है। चीन ने हो हल्ल नहीं किया लेकिन अपने कारोबार को तथा अपनी तकनीकी को लगातार विकसित किया है। भारत के पड़ोसी देशों को चीन ने पिछले एक दशक में बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपना आश्रित बना लिया है। ऐसा करके उसने भारत को चारों ओर से घेर लिया है। चीन को भारत से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। सुनियोजित रणनीति के तहत चीन, भारत को हमेशा कमजोर करके रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। चीन और भारत के संबंध किस सीमा तक हों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चीन के ऊपर भारत की निर्भरता पिछले एक दशक में काफी बढ़ गई है। भारत को अधिकांश आयात चीन से करना पड़ रहा है। भारत का औद्योगिक और उपभोक्ता सामान चीन से ही आता है। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से चीन, भारत के मुकाबले अति ताकतवर है।

वंदे भारत 6 जून से दौड़ेगी कश्मीर तक, चिनाब पुल बनेगा गौरव का प्रतीक



नीट-पीजी 2025 परीक्षा स्थगित, अब एक ही पाली में होगी आयोजित
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया फैसला नई दिल्ली।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने नीट-पीजी 2025 परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के बाद आया है जिसमें परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे एक ही पाली में आयोजित करने को कहा गया था। पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार यह परीक्षा 15 जून 2025 को होनी थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि नई तारीख जल्द अधिसूचित की जाएगी। एनबीईएमएस ने स्पष्ट किया कि परीक्षा स्थगित करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाना और आवश्यक बुनियादी ढांचे को तैयार करना है ताकि न्यायालय द्वारा तय मानकों के अनुसार निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित की जा सके।

संशोधित तिथि की प्रतीक्षा

बोर्ड ने कहा है, कि एनबीईएमएस एक ही पाली में नीट-पीजी 2025 आयोजित करेगा। परीक्षा केंद्रों और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 15 जून को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया है। संशोधित तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।

एक व्यक्ति ने की गुटका साहिब के अंगों की बेअदबी, मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर।

सचखंड श्री दरबार साहिब के बाहर बेअदबी की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद बवाल मच गया। जानकारी के मुताबिक श्री दरबार साहिब के बाहर स्थित श्री गुरु अर्जन देव निवास के पास एक व्यक्ति ने गुटका साहिब के अंगों की बेअदबी की। मौके पर मौजूद संगत ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ का रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी-3 ने बताया कि घट्खारा दिवस के चलते भारी पुलिस बल तैनात है और संगत भी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। जब आरोपी द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, तो संगत ने मौके पर ही उसे दबोच लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।

मौसम-जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में अलर्ट

नई दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल केक लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए तेज बारिश, बर्फबारी और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद अब पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। इसके चलते अधिकतम में भारी गिरावट आई है। श्रीनगर में रविवार को तापमान तापमान सिर्फ 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.5 डिग्री कम है। वहीं गुलमर्ग में तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 9.9 डिग्री नीचे था। पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पहलगाम में भी अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 6.9 डिग्री कम है। यहां तक कि गर्म माने जाने वाले जम्मू में भी पारा गिरकर 35.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और ओले गिरने संभावना जताई है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिससे भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने का खतरा बना हुआ है।

कब कहां होगी बारिश

3 जून- जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में कई जगहों पर बारिश की संभावना।

4 जून- कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछोरे पड़ सकती हैं।

5-6 जून- मौसम रहेगा अधिकतर साफ, लेकिन दोपहर बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

जम्मू।

कश्मीर घाटी को रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का तीन दशकों पुराना सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटड़ा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल, पर भी दौड़ेगी, जो कि एफिल टॉवर से भी ऊंचा है। यहां बताते

काजीगुंड-बनिहाल (18 किमी)-शुरू- जून 2013, तृतीय चरण उधमपुर-कटड़ा (25 किमी)-शुरू- जुलाई 2014, चतुर्थ चरण बनिहाल-संगलदान (48 किमी) - शुरू- फरवरी 2024 और पंचम चरण कटड़ा-संगलदान (63 किमी) - शुरू- 6 जून 2025 है। **इजीनियरिंग की बैकग्राउंड मिसालें**

इस परियोजना में 943 पुल और 36 सुरंगें शामिल हैं। कुल 164 किलोमीटर सफर पुलों और

सुरंगों से होकर गुजरता है। चिनाब ब्रिज – विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है (एफिल टॉवर से अधिक)। अंजी खड्ड पुल – देश का पहला केबल-स्टे रेलवे ब्रिज। टी-1 सुरंग – वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे बनी, जिसका निर्माण पूरा होने में 20 वर्ष लगे। टी-50 सुरंग – भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, लंबाई 12.77 किमी। यह रेल मार्ग सुरक्षा, पर्यटन और

खुद ही कम हो जाएगी जनसंख्या: दुनिया में रह जाएंगे मात्र 10 करोड़ लोग



नई दिल्ली।

दुनिया की जनसंख्या तेजी से बढ़ती गई और फिर ठहराव आया। इसे लेकर कई शोध प्रकाशित होते रहे हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट ने जो दावा किया है, वह चौंकाने वाला है। फिलहाल दुनिया की आबादी 8 अरब है और वर्ष 2300 में यह संख्या तेजी से कम होने लगेगी। 10 करोड़ ही रह जाएगी। उनसे इतर भी कई शोधों में यह कहा जा चुका है कि वर्ष 2100 तक दुनिया की आबादी में तेज गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ष 2050 के बाद से स्थिरता की स्थिति होगी और फिर अगले 50 सालों में इसमें कमी आने लगेगी। अब टेक एक्सपर्ट सुभाष काक का कहना है कि दुनिया की आबादी में यह गिरावट कहीं ज्यादा तेजी से होगी और वर्ष 2300 तक तो महज 10 करोड़ लोग ही रह जाएंगे। इसकी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनेगा। इसकी मदद से लोग बहुत से काम निपटाएंगे और अंत में बच्चे पैदा करने की दर में भी इसके चलते गिरावट आएगी। ओकलाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाले सुभाष काक का कहना है कि जनसंख्या में यह गिरावट किसी न्यूक्लियर अटैक से नहीं आएगी। इसकी वजह यह होगी कि हमारी नौकरियों में कोई एआई रिप्लेस कर देगा। काक ने कहा कि यह समाज और दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अभी तो लोगों को शायद यह भी पता नहीं है कि आगे का एस्ता क्या है। हमें किस दिशा में बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर और रोबोट भले ही संवेदनशील नहीं होंगे, लेकिन यह भी सही है कि हम जो कुछ भी काम आजा कर रहे हैं। उसकी जगह एआई ले सकता है। एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक ने कहा कि भविष्य में जन्म दर कम होगी।

बंगाल की खाड़ी में क्यों आते हैं इतने तूफान, हिंद महासागर में क्यों नहीं



नई दिल्ली।

बीते साल रेमल तूफान ने बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक भयानक तबाही मचाई थी। तूफान के बाद तबाही का एक भयानक मंजर देखने को मिला, गांव के गांव डूब गए। ऐसा पहली बार नहीं था जब बंगाल की खाड़ी में पैदा हुए तूफान ने तबाही मचाई हो इस तरह के तूफान बंगाल की खाड़ी में आते रहे हैं। बंगाल की खाड़ी दुनिया के उन समुद्रों में आता है जहां सबसे ज्यादा तूफान बनते हैं।

हम आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल की खाड़ी में इतने तूफान क्यों आते हैं और हिंद महासागर में तूफान क्यों नहीं आता। दरअसल साल 1891 से 2019 तक बंगाल की खाड़ी में कुल 522 तूफान उठे हैं। अगर हर साल का एक औसत के हिसाब से यहां हर साल औसतन 4 तूफान बनते हैं। सबसे घातक तूफानों की बात करें तो 129 सालों के भीतर 234 तबाही ला देने वाले तूफान बनते हैं। इसकारण बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र बनाता है। अगर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को मिला दें,तब दुनिया का 7 प्रतिशत तूफान दोनों समुद्रों में बनता है। भारत में आने वाले 100 समुद्री तूफानों में सिर्फ 86 प्रतिशत बंगाल की खाड़ी में आता है। हिंद महासागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी के अंदर इसलिए ज्यादा तूफान आते हैं, क्योंकि इसके हवा का बहाव अलग है। हिंद की तुलना में बंगाल की खाड़ी का मौसम ज्यादा गर्म होता है और उठे समुद्र की तुलना में गर्म पानी वाले समुद्र में ज्यादा तूफान आते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठते हैं उसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में दिखाता है। उड़ीसा के अलावा असर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर भी होता है। बंगाल की खाड़ी की सतह का तापमान पूरे साल 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है यह चक्रवात पैदा करने के सक्षम होता है। गर्म पानी से भाप बनती है, जिससे हवा ऊपर उठती है और कम दबाव का क्षेत्र बनता है जो चक्रवात को जन्म देता है।

देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 4,026 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 4 हजार को पार कर गई है, इनकी कुल संख्या 4,026 हो गई है। चिंता की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हुई है। जहां तक राज्यवार कोरोना की स्थिति की बात है तो देश में सबसे ज्यादा केस केरल में 1416 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 494 एक्टिव केस हैं। वहीं गुजरात में 397 एक्टिव केस, दिल्ली में 393 एक्टिव केस (हालांकि 90 मामलों की कमी दर्ज की गई है) है। गुजरात में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 59 नए एक्टिव केस मिले हैं, जो कि इस समय का उच्चतम दैनिक आंकड़ा है। **कोरोना से मौत के आंकड़े**

कोरोना संक्रमण के कारण अब तक जिन 5 लोगों की मौत हुई है, वे इन राज्यों से हैं-

क्या है भविष्य का नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर....जिसके बारे में सीडीएस चौहान ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली।

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा है कि भविष्य में नॉन कॉन्टैक्ट वॉर ही होने है। उन्होंने कहा कि अब आने वाला समय ऐसा ही है, जिसमें सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी और जंग भी हो जाएगी। इसके तहत जल, थल और वायु में लड़ाई होगी ही, इसके अलावा रणनीति, हाइब्रिड वारफेयर, प्रोपेगेंडा जैसी चीजों भी इसका हिस्सा होंगी। उन्होंने कहा कि इसतरह हमें

दरअसल भविष्य की जंगों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार बात करते रहे हैं। वहीं देश के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत भी खई मोर्चे की जंग एक थ्योरी दी दे चुके थे। उनका कहना था कि चीन हमारे लिए पहला खतरा है और दूसरा खतरा पाकिस्तान है। इसके बाद आधा मोर्चा देश की आंतरिक सुरक्षा है। दरअसल बीते कुछ सालों में युद्ध की प्रकृति में बड़ा बदलाव आया है। अब हाइब्रिड वारफेयर का इस्तेमाल बढ़ा है। क्या है नॉन-कॉन्टैक्ट वारफेयर नॉन-कॉन्टैक्ट वारफेयर एक

आधुनिक युद्ध की रणनीति है, इसमें दुश्मन के साथ प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क में आए बिना नुकसान पहुंचाया जाता है या युद्ध लड़ा जाता है। इसमें पारंपरिक युद्ध (जैसे आमने-सामने की लड़ाई) के बजाय आधुनिक तकनीकों, साइबर साधनों, और दूर से संचालित हथियारों का प्रयोग होता है। **नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर की प्रमुख विशेषताएं**

प्रत्यक्ष टकराव नहीं होता, सैनिक आमने-सामने नहीं लड़ते। नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर में तकनीकी साधनों का प्रयोग होता है, जैसे ड्रोन, मिसाइलें, साइबर

मुद्दा उठाती रही हैं और अपनी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना खत्म कर सेना में नौजवानों को स्थाई नौकरी की बातें बार-बार कर रही हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक का एजेंडा सोमवार को जारी किया। गृह विभाग की तरफ से रिटायर अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में आरक्षण का प्रस्ताव आया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2022 में अग्निवीर योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्टैक्ट पर भर्ती किया जाता है। इन चार सालों में छह महीने की ट्रेनिंग होती है। चार साल बाद जवानों को उनकी



कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी रेटिंग और मॉर्गेंट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थाई किया जाता है और अन्य को रिटायर होना पड़ता है। इसी रिटायरमेंट का विपक्षी पार्टियां विरोध करती रही है। उनका कहना है कि हथियारों की ट्रेनिंग देने के बाद नौजवानों को इस तरह से बेरोजगार छोड़ दिया जाता है। माना जा रहा है कि सबसे पहले भर्ती किए गए अग्निवीर अगले साल से रिटायर होने लगेंगे।

पहला कॉलम



असम और पूर्वोत्तर में तेज बारिश के साथ बाढ़ का कहर जारी

5.5 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 40 के पार

गुवाहाटी।

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। असम के 22 जिलों में 5.35 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में एक और मौत की पुष्टि के बाद राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अन्य राज्यों को मिलाकर अब तक करीब 40 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, असम में 1,254 गांव और 65 राजस्व क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक असर श्रीभूमि, कछार और नगांव जिलों में देखा गया है। श्रीभूमि जिले में अकेले 1.94 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सबसे अधिक प्रभावित लखीमपुर जिले का दौरा किया और राहत कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की ओर स्थित रंगनदी बांध से छोड़े गए पानी के कारण डूबे गांवों का निरीक्षण किया। सरमा ने कहा कि अमतोला क्षेत्र में पचनोई नदी का तटबंध टूट जाने से भारी नुकसान हुआ है। 15 नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की जानकारी दी गई है, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में सड़क, रेल और नौका सेवाएं प्रभावित हुई हैं। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे बचाव और राहत कार्यों में बाधाएं आने की आशंका है। सेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। असम में अब तक 165 राहत शिविरों में 31,212 लोग आश्रय ले चुके हैं, और 157 राहत वितरण केंद्र भी सक्रिय हैं। अन्य राज्यों जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और सिक्किम में भी हालात चिंताजनक हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन और रास्तों के बंद हो जाने से राहत कार्यों में परेशानी हो रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

उत्तराखंड में 170 मटरसे सील, प्रशासन ने कहा- ऊपर से आदेश, हुआ विरोध

देहरादून।

उत्तराखंड में मंदरसों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सरकार की ओर से जहां इसे अवैध और बिना मान्यता वाले मंदरसों के खिलाफ अभियान बताया जा रहा है, वहीं मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मई 2025 तक राज्य सरकार द्वारा 170 से अधिक मंदरसे सील किए जा चुके हैं। देहरादून के दारुल उलूम मुहम्मदिया मंदरसा के प्रबंधक मोहम्मद मोतश्मि बताते हैं कि उनके मंदरसे में करीब 70 से 80 बच्चे पढ़ते थे, सभी के पास जमीन के दस्तावेज और शिक्षा बोर्ड की मान्यता है। फिर भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की और सिर्फ इतना कहा, मंदरसा सील होकर रहेगा, ऊपर से ऑर्डर है। इस मामले में प्रशासन और उत्तराखंड मंदरसा बोर्ड का कहना है कि केवल उन मंदरसों पर कार्रवाई की गई है जो बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, 27 फरवरी 2025 को मान्यता समिति की बैठक के बाद ही कुछ मंदरसों की पुरानी और नई एलिकेशनों की समीक्षा की गई थी। हालांकि, सर्टिफिकेट जारी होने से पहले ही कई मंदरसों पर कार्रवाई शुरू हो गई। मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह कार्रवाई सुनिश्चित है और एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। उनका आरोप है कि सरकार का मकसद शिक्षा से जुड़ी इन संस्थाओं को बंद कर मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई बाधित करना है। कई संगठन इस मुद्दे पर प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। मंदरसे सील किए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को धार्मिक भेदभाव और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बताया है। वहीं, सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि यह कानून व्यवस्था और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल है।

देहरादून में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, लड़की को लेकर रंजिश बनी जानलेवा

देहरादून।

राजधानी के भाऊवाला क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी (22) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे एक युवती को लेकर चली आ रही रंजिश कारण बनी।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार तड़के मुजफ्फरनगर निवासी अजहर त्यागी ने किसी बहाने से रोहित को डीबीआईटी चौक पर बुलाया। रोहित अपने दोस्तों के साथ कार से वहां पहुंचा। मौके पर

पहले से मौजूद अजहर और उसके साथी बाइक पर आए हुए थे। बातचीत के दौरान अजहर ने अचानक रोहित के गले पर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रोहित नेगी सेलाकुई क्षेत्र में खनन और प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था और संगठन में सक्रिय भूमिका निभा चुका था।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि रोहित और अजहर के बीच एक युवती को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। युवती रोहित के एक करीबी दोस्त की मित्र बताई जा रही है। घटना की

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी सिटी प्रमोद शाह ने बताया कि आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और चार टीमों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई हैं। मुख्य आरोपी अजहर की पहचान हो चुकी है, जो फिलहाल फरार है। हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हालात बिगड़े, पीएम ने दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

बाढ़ और भूस्खलन 36 की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित

नई दिल्ली।

पूरे देश में मौसम बदल रहा है। कहीं बाढ़ तो कभी तेज बारिश हो रही है तो कहीं लोग गर्मी से बेहाल हैं। उत्तर भारत में अभी मानसून नहीं आया है लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। बाढ़ के कारण मणिपुर, सिक्किम, असम जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी ने बाढ़ से जुड़ा रहे पूर्वोत्तर के राज्यों को हरसंभव मदद की पेशकश की है।

मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों ने मंगलवार को

जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से बात कर स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 36 तक पहुंच गई है, जबकि क्षेत्र के कई राज्यों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

असम के सीएम ने फोन पर पीएम मोदी के साथ

हुई बातचीत में कहा कि असम और आसपास के राज्यों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और इसके कारण लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत अभियान से भी अवगत कराया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की और हमारे राहत एवं पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 11 की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा जिलों में 5.35



लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं।

तुर्किये में भूकंप के झटके: लोग घरों से भागे, कुछ ने बालकनी से लगाई छलांग, 7 घायल

मारमारिस।

तुर्किये के भूमध्यसागर तट पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। तट से सटे शहर मारमारिस में सोमवार देर रात भूकंप आया। जैसे ही लोगों ने झटके महसूस किए वो डर कारण घर छोड़कर भागने लगे। कईयों ने जल्दबाजी में घर की बालकनी से छलांग लगा। इस भगदड़ में करीब 7 लोग घायल हुए हैं। भूकंप के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि पूरा घर हिल रहा है।

तुर्किये में भूमध्यसागर से सटे तटीय शहर मारमारिस में सोमवार देर रात 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्किये की आपदा प्रबंधन एजेंसी की ओर से यह जानकारी दी गई है।

भूकंप के कारण घरबाराकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगे जिससे कम से कम सात लोग घायल हो गए। भूकंप के दौरान लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि सीलिंग में लगी लाइट जोर से हिल रही है। वीडियो बना रहा शख्स दहशत में है।

तुर्किये की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी 'डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसीडेंसी' ने कहा कि भूकंप का केंद्र भूमध्य सागर में था और यह देर रात दो बजकर 17 मिनट पर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक रोड्स के ग्रीक द्वीप सहित आसपास के क्षेत्रों



में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मारमारिस के गवर्नर इदरीस अकबीविक ने बताया कि घरबाराह में लोग अपने घरों की खिड़कियों या बालकनियों से कूदने लगे जिसके कारण सात लोगों घायल हो गए। हालांकि किसी भी तरह की गंभीर क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है।

तुर्किये भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है और यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तुर्किये में 2023 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसके कारण 53,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और देश के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व के 11 प्रांतों में सैकड़ों इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

फिल्म निर्देशक सनोज बोला- न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अपना लूंगा

मुंबई।

फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म में मौका देने के लिए चर्चा में आए थे, अब एक नए विवाद के केंद्र में हैं। हाल ही में जेल से छूटे मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे परिवार सहित हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लेंगे। गौरतलब है कि फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा पर पूर्व में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वह कुछ समय के लिए जेल में भी रहे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया। उन्होंने इस साजिश के पीछे बसोम रिजजी उर्फ जितेंद्र त्यागी का नाम लिया है। इसी के साथ मिश्रा ने कहा, कि यदि प्रशासन ने मेरी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की और मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अयोध्या जाकर सार्वजनिक रूप से धर्म परिवर्तन करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। मिश्रा के आरोपों और उनके बयानों की सत्यता की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही की जा सकेगी।

खालिस्तान मुद्दा बना सबसे बड़ा अवरोधक

भारत की प्रमुख चिंता है कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्व और उनका खुलेआम समर्थन। रिपोर्ट्स के अनुसार, कनाडा की नई सरकार पर खालिस्तान समर्थकों ने दबाव डाला कि पीएम मोदी को जी7 सम्मेलन के लिए निर्मंत्रण न भेजा जाए। यह वही मुद्दा है जो भारत की किसी भी उच्च स्तरीय बातचीत या यात्रा को अवरुद्ध करता है।



संबंधों में तीखा टकराव हुआ, और एक-दूसरे के राजनयिकों को निकालसित किया गया।

कनाडा में सरकार बदली, पर हालात नहीं

अप्रैल 2025 में कनाडा में चुनाव हुए और मार्क कार्नी की सरकार बनी। इससे संबंधों में सुधार की कुछ उम्मीदें जगी थीं। विदेश मंत्री अनिता आनंद और एस. जयशंकर के बीच फोन पर बातचीत भी हुई, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर रिशते पटरी पर लौटते नहीं दिख रहे हैं।

जमुई स्टेशन पर जसीडीह ईएमयू ट्रेन में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जमुई।

बिहार के जमुई रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म पर खड़ी जसीडीह ईएमयू पैसेंजर ट्रेन के दो कोचों को जोड़ने वाली कनेक्शन पाइप से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्री इधर-उधर भागने लगे। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, स्टेशन पर रखे पांच अग्निशमन सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गए। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। इससे पहले प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकते ही यात्रियों ने जब धुआं देखा तो भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि, रेलवे अधिकारियों और पुलिस द्वारा समय पर माइकिंग कर यात्रियों को शांत किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक जांच में यह तकनीकी खामी प्रतीत हो रही है, हालांकि विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही असली कारण का खुलासा होगा।

ऑनलाइन सट्टे ने ले ली जान, कर्ज में डूबे युवक ने पत्नी संग की खुदकुशी

कोटा।

कैथून कस्बे में सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 5 लाख रुपये के ऑनलाइन गेमिंग कर्ज में डूबे एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। दोनों के शव कर्मरे में पंखे से लटके मिले, जबकि पांच साल की मासूम बेटी कमरे में मौजूद थी और उसी ने दरवाजा खोलकर परिजनों को भीतर का मंजर दिखाया। मृतकों की पहचान दीपक राठौर और उनकी पत्नी राजेश राठौर के रूप में हुई है। पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, दीपक ने आत्महत्या से एक दिन पहले अपनी साली को फोन कर बताया था कि वह ऑनलाइन सट्टे के गेम में 4 से 5 लाख रुपये हार चुका है और अब उसके पास मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। साली ने उसे समझाने की कोशिश की और पैसों का इंतजाम कराने का आश्वासन भी दिया, लेकिन अगले ही दिन दुखद घटना की खबर आ गई। मृतक दीपक के पिता सत्यनारायण राठौर का कहना था, कि उनका इकलौता बेटा था और उसके साथ पत्नी और बेटी रहते थे। रविवार रात सबने साथ खाना खाया और सामान्य रूप से सोने चले गए। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने खटखटया। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुछ देर बाद मासूम पोती ने दरवाजा खोला। भीतर का दृश्य देख सबके होश उड़ गए।

बैंकिंग इतिहास की सबसे सनसनीखेज लूट, सोना चोरी कर चोर छोड़ गए काली गुड़िया

केनरा बैंक की शाखा में हुई वापदात, कोई गिरफ्तारी नहीं

नई दिल्ली।

भारत में अब तक की सबसे बड़ी बैंक लूट की घटना सामने आई है।

कर्नाटक के विजयपुर जिले की मनागुली स्थित केनरा बैंक शाखा से चोरी ने 52 करोड़ रुपये मूल्य का सोना लूट लिया। चोर 51 किलोग्राम सोने के आभूषण लेकर

फरार हो गए। यह घटना 23 से 25 मई के बीच अंजाम दी गई और इसका खुलासा तब हुआ जब बैंक कर्मचारी 26 मई को कार्यस्थल पर लौटे। पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी के मुताबिक, यह चोरी एक सुनियोजित साजिश थी। चोरों ने लंबे सप्ताहांत की छुट्टियों का फायदा उठाया। पुलिस को अब

तक जिन तथ्यों का पता चला है, उसके अनुसार, चोर नकली चाबी से बैंक में दाखिल हुए थे और उन्होंने सुरक्षा अलार्म निष्क्रिय कर दिए थे। सीसीटीवी के कैमरे और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर चोरी कर लिए। इस चोरी में केवल लॉकर सेबशन को ही निशाना बनाया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि चोर जाते-जाते एक काली

गुड़िया छोड़ गए, जिससे इस घटना को अब कथित तौर पर काले जादू या अंधविश्वास से जोड़कर देखा जा रहा है।

चोरी के पीछे 6-8 लोगों का संदेह, 8 टीमों जांच में जुटी

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 विशेष टीमों गठित की हैं। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी

है और यह पता नहीं चल पाया है कि चोर सोना लेकर कैसे फरार हुए।

वैसे यह पहली बार नहीं है जबकि कर्नाटक में चोरी द्वारा बैंक को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 28 अक्टूबर 2023 को दावणगेरे के न्यामथी में एसबीआई से 13 करोड़ का सोना चोरी हुआ था।